



BACKGROUNDERS

Press Information Bureau

Government of India

सहायक क्षेत्र और बाजार तक पहुंच को मिल रही मजबूती

भारत के पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में आ रहा बदलाव

01 मार्च, 2026

मुख्य बातें

- खेती और उससे जुड़े क्षेत्र 3-5% सीएजीआर दर से लगातार बढ़े हैं, जबकि पशुधन और मछली पालन सालाना 5-6% की दर से तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे गांवों में आय के विविधीकरण को मजबूती मिली है।
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है, जिसका उत्पादन 146.31 एमटी (2014-15) से बढ़कर 247.87 एमटी (2024-25) हो गया है, जो 69% की वृद्धि दिखाता है।
- अंडे के उत्पादन में भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, जिसका उत्पादन 78.48 बिलियन से बढ़कर 149.11 बिलियन अंडे हो गया है, जबकि प्रति व्यक्ति उपलब्धता 62 से बढ़कर 106 अंडे सालाना हो गई है।
- भारत दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, जिसका उत्पादन 9.58 एमटी से बढ़कर 19.77 एमटी हो गया है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% का योगदान देता है और 30 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है।
- मीट का उत्पादन 6.69 एमटी से बढ़कर 10.50 एमटी हो गया, जिससे भारत दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया।
- आम बजट 2026-27 में मछली पालन के लिए ₹2,761.80 करोड़ और एमओएचएंडडी D को ₹6,153.46 करोड़ दिए गए (16% की बढ़ोतरी), जिससे क्षेत्र में लगातार निवेश को बढ़ावा मिला।

परिचय

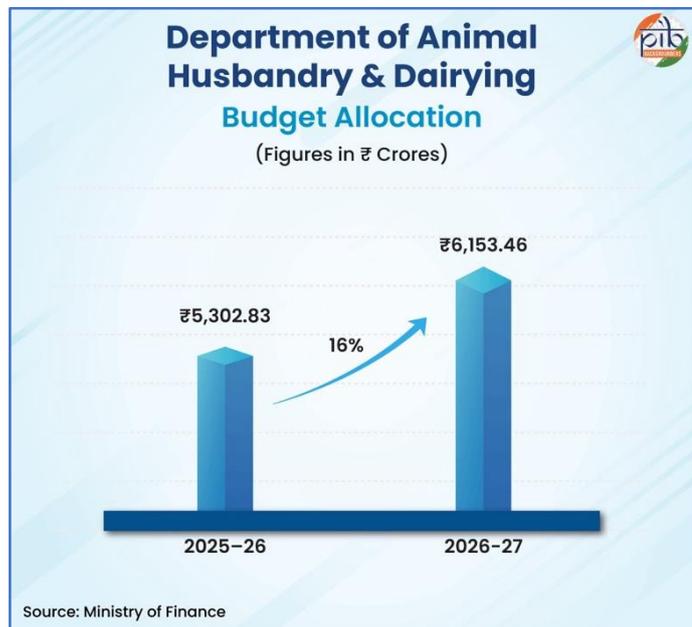
भारत में खेती की विकास को पशुधन, डेयरी, पोल्ट्री और मछली पालन जैसे जुड़े हुए क्षेत्रों के बढ़ने से तेजी से मदद मिल रही है। ये क्षेत्र खेती के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) और ग्रामीण रोजगार में बड़ा योगदान देने वाले बन गए हैं। पिछले दशक में, खेती और जुड़े हुए सेक्टर में लगातार 3-5% सीएजीआर देखा गया है, जिसे बड़े सरकारी प्रयासों, निजी क्षेत्र के नवाचार और बड़ी घरेलू मांग से बढ़ावा मिला है। अनुमान है कि 2047 तक, यह क्षेत्र शायद तीन गुना बढ़ सकता है, जिससे भारत के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भले ही, गांवों में आजीविका ज्यादातर खेती पर ही आधारित है, लेकिन जमीन के इस्तेमाल में बदलाव, मौसम में बदलाव और आय की अनिश्चितता ने परिवारों को आय के अतिरिक्त स्रोत अपनाने के लिए बढ़ावा दिया है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए, विविधीकरण मौसमी आय में उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करने और ज्यादा स्थिर कमाई सुनिश्चित करने का एक जरूरी तरीका बन गया है।

विविधीकरण में खेती, जुड़े हुए और गैर-कृषि कार्यों से होने वाली इनकम शामिल है ताकि जोखिम कम हो और घरेलू खपत आसान हो। खेती से दूर जाने के बजाय, यह एक ज्यादा एकीकृत और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दिखाता है जहां खेती केंद्र में रहती है लेकिन इसे आजीविका के कई विकल्प मिलते हैं। सहकारिता, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) जैसे मजबूत संस्थानों ने क्रेडिट, प्रौद्योगिकी और संगठित बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाया है, जिससे छोटे उत्पादक मूल्य श्रृंखला से बेहतर तरीके से जुड़ पाए हैं।

पशुधन और मछली पालन: ग्रामीण आय विविधीकरण और वृद्धि के कारण

खेती से जुड़े कामों में, पशुधन और मछली पालन ने लगभग 5-6 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि दर दिखाई है, जो ग्रामीण आय पैदा करने में उनके रणनीतिक महत्व को दिखाता है। उनका आर्थिक महत्व नियमित और तुलनात्मक रूप से अनुमानित नकदी प्रवाह पैदा करने में है। दुग्ध उत्पादन से नियमित दूध की बिक्री से लगातार आय होती है, जबकि मछली पालन से कई उत्पादन चक्र मुमकिन होते हैं, जिससे लगातार रोजगार के मौके मिलते हैं। इसके अलावा, डेयरी पर आधारित ग्रामीण परिवार आमतौर पर खाने और चारे के लिए फसल की खेती को पशुधन पालन के साथ मिलाते हैं, जिससे संसाधन का



सर्कुलर इस्तेमाल मुमकिन होता है और बाहरी इनपुट पर निर्भरता कम होती है। इस तरह के विविधीकरण से आय के एक ही स्रोत पर निर्भरता कम होती है और मौसमी और बाजार के झटकों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।

वित्त वर्ष 15 और वित्त वर्ष 24 के बीच, इस क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) लगभग 195 प्रतिशत बढ़ा, जो मौजूदा कीमतों पर 12.77 प्रतिशत की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) दिखाता है। आम बजट 2026-27 में, पशुपालन और डेयरी विभाग को ₹6,153.46 करोड़ दिए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2025-26 के ₹5,302.83 करोड़ से 16 प्रतिशत ज्यादा है। यह बढ़ती आय के विविधीकरण और आजीविका की मजबूती में सेक्टर की भूमिका को दिखाती है, जिसे नस्ल सुधार, पशु चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और बीमारी कंट्रोल में निवेश से समर्थन मिलता है।

पशुधन और मछली पालन में भारत एक वैश्विक लीडर

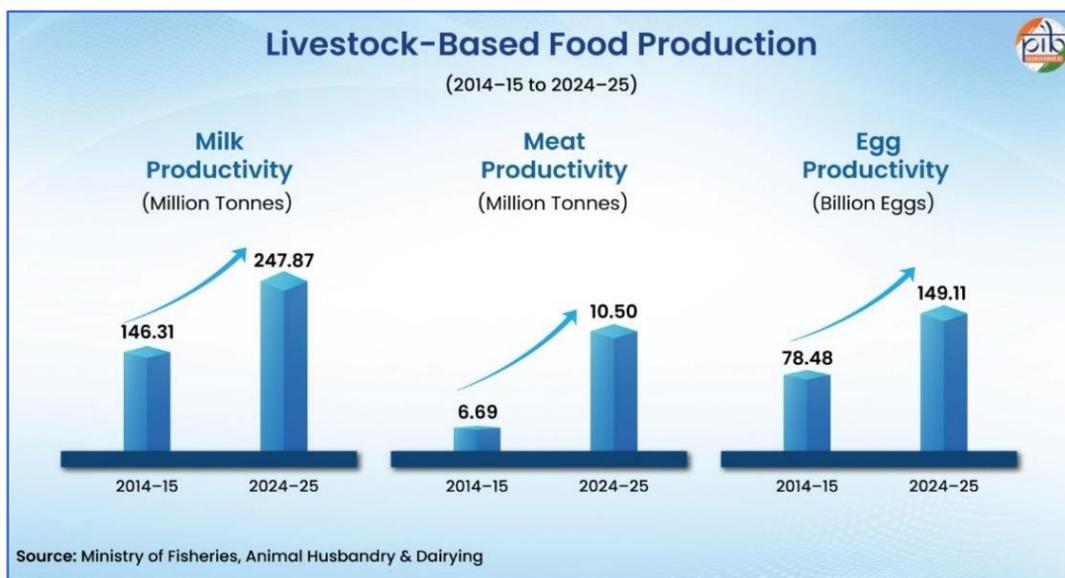
भारत दूध उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है और दुनिया भर में होने वाले कुल उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा यहीं से आता है। पिछले एक दशक में, इस क्षेत्र में 5.41 प्रतिशत की कंपाउंड सालाना ग्रोथ रेट दर्ज की गई है, जिसमें उत्पादन 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 247.87 मिलियन टन हो गया है, जो 69.4 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दिखाता है। इस लगातार बढ़ती ने पोषण तक पहुंच को बेहतर बनाने में मदद की है, जो 2024-25 में हर दिन 485 ग्राम दूध की उपलब्धता में दिखता है, जो दुनिया भर के औसत 328 ग्राम से काफी ज्यादा है।

अंडे के उत्पादन में भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। देश का उत्पादन 2014-15 में 78.48 बिलियन अंडों से बढ़कर 2024-25 में लगभग 149.11 बिलियन अंडों तक पहुंच गया है, जो एक दशक से ज्यादा समय में 6.63 प्रतिशत की कंपाउंड सालाना ग्रोथ रेट (सीएजीआर) दिखाता है। इस निरंतर विस्तार से पोषण तक पहुंच में सुधार हुआ है, जिससे प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता 2014-15 में 62 अंडे प्रति वर्ष से बढ़कर 2024-25 में 106 अंडे प्रति वर्ष हो गई है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। वित्त वर्ष 2013-14 में 9.58 मिलियन टन से वित्त वर्ष 2024-25 में आउटपुट बढ़कर 19.77 मिलियन टन हो गया है। यह वैश्विक उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत का



योगदान देता है और 30 मिलियन से ज्यादा लोगों की आजीविका को समर्थन देता है, जिससे यह ब्लू इकोनॉमी का एक अहम स्तंभ बनता है। तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें लगभग 4,434 मछली पकड़ने वाले गांव शामिल हैं, की उत्पादन में 72 प्रतिशत और सीफूड निर्यात में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह क्षेत्र कृषि जीविए में 7.43 प्रतिशतका योगदान देता है, जिसमें मुख्य मछली उत्पादों पर जीएसटी कम करने और घरेलू मांग और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने जैसे नीतिगत उपाय शामिल हैं।



मीट प्रोडक्शन में भारत दुनिया भर में चौथे नंबर पर है। 2014-15 में उत्पादन 6.69 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 10.50 मिलियन टन हो गया है, जो 4.61 प्रतिशत की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) दिखाता है। कुल मिलाकर, ये संकेतक घरेलू और वैश्विक कृषि-खाद्य अर्थव्यवस्था में एक बड़े योगदानकर्ता के तौर पर भारत की अहम जगह की पुष्टि करते हैं।

पशुधन उत्पादकता के लिए नीतिगत हस्तक्षेप

भारत के पशुधन क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम), राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम), और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) जैसी पहलों के जरिए सरकार के खास दखल से हुआ है, जो उत्पादकता में सुधार, जानवरों की सेहत, नस्ल के विकास और पशुधन पर आधारित उद्यमशीलता पर जोर देते हैं। इन सभी पहलों ने मिलकर पशुधन व्यवस्था को मजबूत किया है, उत्पादकता के जोखिम कम किए हैं और ग्रामीण परिवारों के लिए पशुधन को आय का एक मजबूत और अलग-अलग तरह का स्रोत बनाया है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन पशुधन पर आधारित उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है, नस्ल की उत्पादकता में सुधार करता है, और मांस, अंडे, दूध और चारे का उत्पादन बढ़ाता है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन देसी गायों की नस्लों को बचाने, दूध की उत्पादकता बढ़ाने और गांव के किसानों के लिए दूध को ज्यादा फायदेमंद बनाने पर फोकस करता है।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों को एफएमडी के खिलाफ 100% टीकाकरण और सभी मादा गाय के बछड़ों (4-8 महीने) को ब्रूसेलोसिस के खिलाफ टीकाकरण के जरिए फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी) और ब्रूसेलोसिस को नियंत्रित करने पर फोकस करता है।

कृत्रिम गर्भाधान के जरिए जेनेटिक सुधार और कोने-कोने में सेवाओं की डिलीवरी

आरजीएम के तहत जेनेटिक सुधार के उपायों ने पशुधन सेक्टर में उत्पादकता से होने वाली वृद्धि को मजबूत किया है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

- कुल 14.56 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं, जिसमें 9.36 करोड़ जानवरों को कवर किया गया और 5.62 करोड़ किसानों को फायदा हुआ।
- लगभग 39,810 एमएआईटीआरआई (MAITRI) कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के प्रशिक्षण ने लास्ट-माइल सर्विस डिलीवरी को मजबूत किया है।

इन उपायों से जेनेटिक फायदे तेजी से हुए हैं, दूध की पैदावार बेहतर हुई है और डेयरी से होने वाली आजीविका से आय की संभावना मजबूत हुई है।

पशु स्वास्थ्य को बेहतर और जोखिम कम करना

पशुओं की उत्पादकता और आय की स्थिरता बीमारी नियंत्रण के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। एनएडीसीपी के तहत, बड़े पैमाने पर टीकाकरण और निगरानी की कोशिशों से बीमारी के मामलों में काफी कमी आई है। 125.75 करोड़ से ज्यादा फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी) के टीके लगाए गए और लगभग 26.27 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। 2025 में टीकाकरण कवरेज को बढ़ाकर इसमें चरवाहे भेड़ और बकरियां भी शामिल की गईं।

- एफएमडी के मामले 2019 में 132 मामलों से तेजी से कम होकर 2025 में 6 मामले रह गए।
- ब्रूसेलोसिस के मामले जीरो हो गए हैं।

बीमारी के मामलों में कमी से उत्पादकता में होने वाले नुकसान में कमी आई है।

पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने से आजीविका में विविधता लाने में मदद मिली

Did You Know

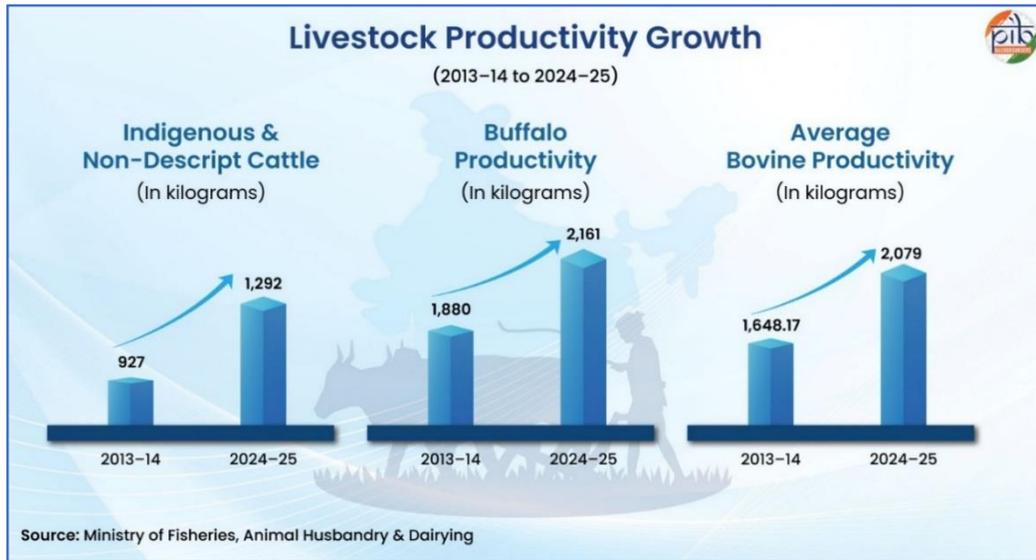
Foot and Mouth Disease is a highly contagious viral disease affecting animals such as cattle, buffaloes, sheep, goats, and pigs. It affects milk yield, slows growth, and impairs reproduction.

Brucellosis is a bacterial disease in cattle and buffaloes that affects the reproductive system, leading to infertility, abortions, and reduced milk production.

जेनेटिक और स्वास्थ्य से जुड़े उपायों का मिला-जुला असर गोजातीय उत्पादकता में लगातार सुधार के रूप में दिखता है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी गोजातीय आबादी है और यहां मीट और पोल्ट्री उत्पादन में काफी बढ़ोतरी देखी गई है।

- देसी (लोकल) और गैर वर्गीकृत (मिश्रित नस्ल) मवेशियों की उत्पादकता 927 किग्रा प्रति जानवर प्रति साल (2014-15) से बढ़कर 1,292 किग्रा (2023-24) हो गई, जो 39.37 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।
- भैंसों की उत्पादकता 1,880 किग्रा से बढ़कर 2,161 किग्रा हो गई, जिसमें इसी समय के दौरान 14.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- गायों की औसत उत्पादकता 1,648.17 किग्रा (2013-14) से बढ़कर 2,079 किग्रा (2024-25) हो गई, जो 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है।

उत्पादकता में ये बढ़ोतरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा दर्ज सुधारों में से एक है और डेयरी से होने वाली आजीविका से सीधे तौर पर आय को बढ़ाती है।



दूध की खरीद और प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाना

डेयरी कोऑपरेटिव के विस्तार ने छोटे किसानों को संगठित खरीद और प्रोसेसिंग प्रणाली में शामिल करके बाजार एकीकरण को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है।

डेयरी नेटवर्क में शामिल हैं:

- 22 मिल्क फेडरेशन, 241 जिला यूनियन, 28 मार्केटिंग डेयरियां,
- 25 दुग्ध उत्पादक संगठन (एमपीओ), जो लगभग 2.35 लाख गांवों और 1.72 करोड़ किसान-सदस्यों को कवर करते हैं।
- 31,908 दुग्ध सहकारी समितियां बनाई गई हैं, जो 17.63 लाख उत्पादकों को औपचारिक मूल्य श्रृंखला में जोड़ती हैं और रोजाना दूध की खरीद में 120.68 लाख किलोग्राम की बढ़ोतरी करती हैं।
- भारत 2028-29 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को मौजूदा 660 लाख लीटर प्रति दिन से बढ़ाकर 100 मिलियन लीटर प्रति दिन करने की योजना के ज़रिए मूल्य वर्धन को मजबूत कर रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा और खेती से होने वाली आय में इस क्षेत्र का योगदान मजबूत होगा।



पशुओं के लिए संस्थागत ऋण सहायता

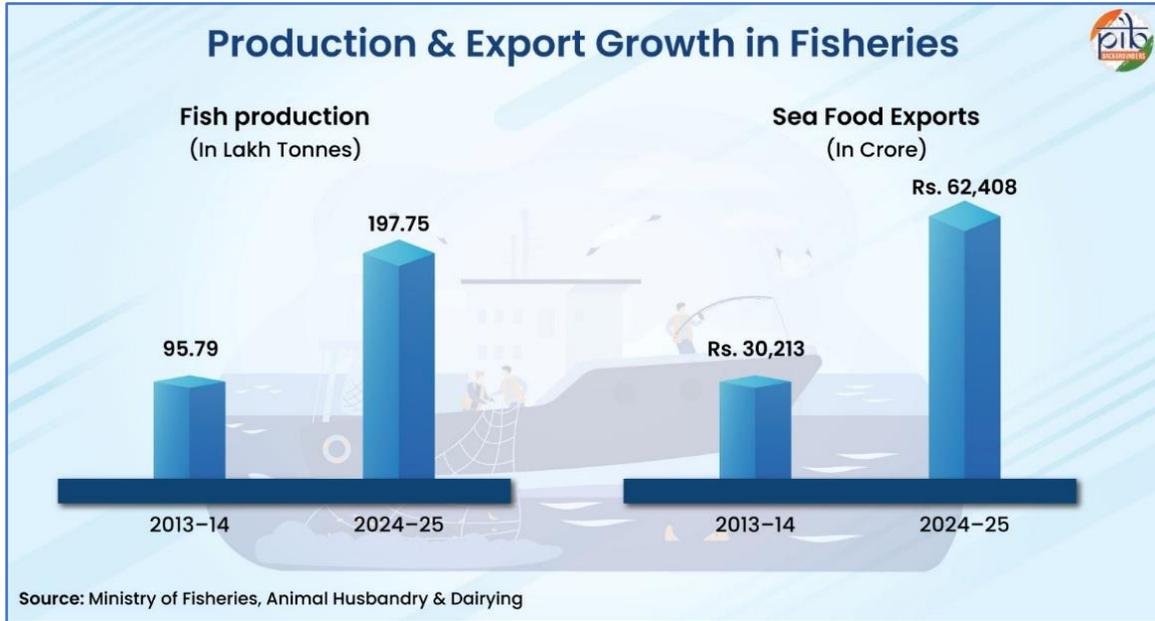
सस्ते संस्थागत ऋण तक पहुंच, पशुओं और मछली पालन सेक्टर में आजीविका में विविधता लाने में मददगार रही है, जिससे उत्पादकों को गुजारे के काम से औपचारिक बाजार एकीकरण में बदलाव करने में मदद मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत, कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने, संपत्ति बनाने को बढ़ावा देने और अनौपचारिक ऋण चैनलों पर निर्भरता कम करने के लिए संबंधित कामों को काफी ऋण सहायता दी गई है। तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि संबंधित खेती के कामों में ऋण की मांग पर संस्थागत प्रतिक्रिया मजबूत है।

पशुपालन में, 55.9 लाख आवेदनों में से 55.08 लाख की बहुत ज्यादा स्वीकृति दर, असरदार स्क्रीनिंग व्यवस्था और लगातार नीतिगत समर्थन को दिखाती है। 39.22 लाख आवेदनों को मंजूरी मिलना भी काफी ऋण प्रवाह का संकेत देता है, जो असल वित्तीय समर्थन में बदल जाता है।

भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए नीतिगत हस्तक्षेप

पिछले दशक में, भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र ने 8.74 प्रतिशत की लगातार औसत सालाना ग्रोथ रेट दर्ज की है, जिसमें कुल मछली उत्पादन 2013-14 में 95.79 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया है। इसी समय के दौरान 61.36 लाख टन से 151.60 लाख टन तक 147 प्रतिशत

की बढ़ोतरी के साथ, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) इस बढ़ोतरी के मुख्य कारण रहे हैं।



आम बजट 2026-27 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड ₹2,761.80 करोड़ (लगभग USD 332.75 मिलियन) दिए गए, जिससे नीली क्रांति (ब्लू रेवोल्यूशन) के तहत शुरू किए गए लगातार निवेश को मजबूती मिली और एक्वाकल्चर और सीफूड निर्यात में भारत की लीडरशिप मजबूत हुई। यह प्रगति गैर कृषि आजीविका विविधीकरण के अंदर, खासकर ग्रामीण और तटीय इलाकों में, मत्स्य पालन को एक मुख्य ग्रोथ इंजन के तौर पर दिखाती है।

डीप-सी और ऑफशोर फिशरीज भारत को वैश्विक सीफूड मूल्य श्रृंखला में और एकीकरण करती है, जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक और खाद्य सुरक्षा की अहमियत और मजबूत होती है। इस एकीकरण को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के तहत खास हस्तक्षेप के जरिए और मजबूत किया गया है, जिसके तहत सीफूड निर्यात 2013-14 में ₹30,213 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹62,408 करोड़ हो गया है, और यह 130 से ज्यादा देशों तक पहुंच रहा है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करके मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देती है ताकि उत्पादन, निर्यात, नौकरियां और मछुआरों की आय बढ़े।

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएम-केएसएसवाई), पीएमएमएसवाई की एक उप-योजना है। यह मछली पालने वालों के लिए आय सुरक्षा और स्थायित्व को बेहतर बनाने के लिए बीमा, ऋण, प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन और ट्रेसेबिलिटी के जरिए क्षेत्र को औपचारिक बनाने में मदद करती है।

मत्स्य पालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार तक पहुंच को मजबूत करना

पीएमएसएसवाई के तहत, उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ-साथ बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है ताकि कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाया जा सके।

- 27,189 मछली ढुलाई और हैंडलिंग इकाइयां बनाई गईं
- 6,733 मछली खुदरा बाजार और कियोस्क मंजूर किए गए
- 128 वैल्यू-एडेड एंटरप्राइज़ यूनिट्स को समर्थन दिया गया

इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने के लिए, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ), जिसे 2018-19 में ₹7,522.48 करोड़ के फंड के साथ लॉन्च किया गया था, फिशिंग हार्बर, लैंडिंग सेंटर, एक्वाकल्चर इकाइयों और कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स को समर्थन देता है।

मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण सहायता

मत्स्य पालन क्षेत्र में, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत 6.83 लाख आवेदन मिले, जिनमें से 6.77 लाख स्वीकार किए गए। इनमें से 4.82 लाख आवेदन मंजूर किए गए, जिससे मांग को ऋण तक पहुंच में बदलने के संकेत मिलते हैं। वित्तीय समावेशन और कल्याण कार्यक्रम ने 4.39 लाख मछुआरों को केसीसी का फायदा दिया है, 3.3 मिलियन लाभार्थियों को बीमे का कवरेज दिया है, और मुश्किल समय में औसतन 7.44 लाख मछुआरे परिवारों को रोजी-रोटी में मदद दी है। ये उपाय दिखाते हैं कि लचीलापन बढ़ाने, आय में स्थायित्व लाने और संगठित बाजार के साथ एकीकरण को गहरा करने में औपचारिक ऋण की क्या भूमिका है।

समुद्री मछली पालन और ईईजेड संसाधनों का सतत शासन

भारत का 11,099 किमी से ज्यादा का बड़ा समुद्र तट और लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) 13 समुद्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मछली पकड़ने वाले समुदाय के 50 लाख से ज्यादा सदस्यों की आजीविका चलाता है। समुद्री मछली पालन ब्लू इकॉनमी का एक रणनीतिक हिस्सा है, जो निर्यात से होने वाली कमाई और राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा में योगदान देता है।

पानी के संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने ईईजेड और हाई सीज में मछली पालन के सतत इस्तेमाल के लिए नियम और गाइडलाइन (2025) अधिसूचित किए हैं, जिससे सतत और अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन मानकों के साथ एक आगे की सोच वाला नियामकीय तंत्र बनाया गया है। विदेश में पकड़ी गई और निर्यात मानी जाने वाली मछलियों को ड्यूटी-फ्री दर्जा देने वाले नीतिगत उपायों का उद्देश्य कीमत वसूलना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, जबकि ट्रेसेबिलिटी, स्थायित्व और अनुपालन सुरक्षा के दुरुपयोग को कम करते हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) गुणवत्ता गुणवत्ता आश्वासन, बाजार की सहूलियत, क्षमता विकास और पारिस्थितिक प्रबंधन के जरिए टिकाऊ निर्यात वृद्धि को और मजबूत करती है, जिससे लंबे समय तक संसाधन सुरक्षा और आजीविका को मजबूती मिलती है।

मिशन-आधारित जलाशय विकास और मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला विस्तार

भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े अंतर्देशीय जलाशय नेटवर्क में से एक है, जो लगभग 31.5 लाख हेक्टेयर में फैला है, जिसमें अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ाने की काफी संभावना है। मिशन अमृत सरोवर के तहत, भारत सरकार ने 68,827 अमृत सरोवरों के विकास में मदद की है, जिसमें मत्स्य पालन गतिविधियों के साथ एकीकृत 1,222 वॉटर बॉडीज शामिल हैं, जिससे फिश कल्चर, आजीविका विविधता और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने को बढ़ावा मिला है। खास तौर पर तटीय और अंतर्देशीय इलाकों में मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को और मजबूत करने के लिए 500 जलाशय और अमृत सरोवरों के विकास को एकीकृत करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप प्रस्तावित हैं। ये उपाय स्टार्टअप्स, महिलाओं के नेतृत्व वाले कलेक्टिव्स और मत्स्य पालक किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) को शामिल करके मार्केट लिंकेज और मूल्य वर्धन को मजबूत करने, समावेशी विकास, उद्यमशीलता और मत्स्य पालन आधारित सतत आजीविका को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं।

पशुधन और मछली पालन सेक्टर में डेटा आधारित संस्थागत सुधार

डेयरी सेक्टर में दक्षता, पारदर्शिता और उत्पादकों की भलाई के लिए डिजिटलीकरण एक जरूरी तरीका बन गया है। 12-डिजिट की विशेष पशुधन पहचान प्रणाली, पशु आधार की शुरुआत ने जानवरों की स्वास्थ्य, प्रजनन और सर्विस डिलीवरी ट्रांज़ेक्शन को दर्ज करने के लिए एक बुनियादी डिजिटल ढांचा बनाया है, जिससे किसानों और जानवरों के डॉक्टरों के लिए डेटा आधारित योजना और रियल-टाइम एक्सेस मुमकिन हुआ है।

जनवरी 2026 तक, भारत पशुधन पोर्टल पर 36.45 करोड़ से ज्यादा पशुधन पंजीकृत हो चुके थे। इसके साथ ही, ऑटोमैटिक मिलक कलेक्शन सिस्टम (एएमसीएस) ने ऑटोमेटेड क्वालिटी टेस्टिंग और प्राइसिंग के जरिए खरीद में पारदर्शिता को बेहतर बनाया है, जिससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है।

इंटरनेट-बेस्ड डेयरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम (आई-डीआईएस) यूनियनों और फेडरेशन के बीच डेटा को और एकीकृत करता है, जिससे प्रदर्शन की निगरानी मुमकिन होती है।

- 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित,
- एएमसीएस 26,000 से ज्यादा सहकारि समितियों को कवर करता है और 17.3 लाख उत्पादकों को फायदा पहुंचाता है।

मछली पालन में डिजिटल सुधारों में नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) शामिल है, जिसे 2024 में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के तहत लॉन्च किया गया था। एनएफडीपी मछुआरों और एंटरप्राइज के लिए डिजिटल पहचान और एक यूनिफाइड नेशनल डेटाबेस बनाता है, जिससे ऋण, बीमा, ट्रेसेबिलिटी और प्रदर्शन प्रोत्साहन तक पहुंच आसान हो जाती है। 28 लाख से ज्यादा हितधारक पंजीकृत हैं, 12 बैंक एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत हुए हैं और 217 लोन बांटे गए हैं, यह प्लेटफॉर्म मछली पालन मूल्य श्रृंखला में फॉर्मलाइजेशन, वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलकर बाजार एकीकरण को मजबूत कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर रहे हैं और आय की निश्चितता में सुधार कर रहे हैं।

सतत समुद्री और डेयरी अर्थव्यवस्था: समावेशी विकास और एसडीजी को आगे बढ़ाना

भारत की समुद्री और डेयरी अर्थव्यवस्था, टिकाऊ रोजगार, पोषण सुरक्षा और समावेशी विकास के बुनियादी आधार हैं, जो सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जुड़े हुए हैं। एसडीजी 14 के साथ समुद्री संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन, खास तौर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का ईईजेड 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, जिससे गहरे समुद्र और ऑफशोर मछली पालन का असरदार प्रबंधन जरूरी हो गया है ताकि ज्यादा इस्तेमाल को रोका जा सके, जैव विविधता को बचाया जा सके और खाने और रोजगार की सुरक्षा को सुरक्षित रखा जा सके।

इसके साथ ही, डेयरी क्षेत्र लगभग 150 मिलियन किसानों, खासकर छोटे किसानों की रोजगार को बनाए रखकर कई सोशल एसडीजी को आगे बढ़ाता है, जिससे गरीबी कम करने (एसडीजी 1), उत्पादक रोजगार (एसडीजी 8) और असमानता कम करने (एसडीजी 10) में मदद मिलती है। कुल मिलाकर, टिकाऊ मछली पालन और सबको साथ लेकर चलने वाला डेयरी विकास, मुख्य सतत विकास के लक्ष्यों में एक साथ और बराबर तरक्की को मजबूत करते हैं।

निष्कर्ष

डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र के जरिए आजीविका में विविधता लाने पर भारत के रणनीतिक जोर ने ग्रामीण परिवारों को गुजारे के लिए जरूरी उत्पादन से बाजार एकीकृत, व्यावसायिक रूप से फायदेमंद

मॉडल में सफलतापूर्वक बदल दिया है। खेती से होने वाली आय बढ़ाने के अलावा, विविधतापूर्ण रोजगार पैदा करने, जोखिम कम करने और खाद्य प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करता है। भारत दूध उत्पादन में दुनिया का लीडर बनकर उभरा है और मछली और अंडा प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है, जिसने झुंड का साइज बढ़ाए बिना ही उत्पादकता में काफी बढ़ोतरी हासिल की है। कोऑपरेटिव, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बढ़ने से बाजार एकीकरण गहरा हुआ है, जिससे छोटे उत्पादकोंको बेहतर मोलभाव करने की ताकत और व्यवस्थित मूल्य श्रृंखला मिली हैं।

पशु आधार और नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल के साथ-साथ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के बढ़ने से पारदर्शिता बढ़ी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हुई है, और ग्रामीण उत्पादकों को जरूरी तरलता मिली है। ये क्षेत्र महिलाओं और छोटे किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण, बड़े पैमाने पर आजीविका को समर्थन देने और गरीबी कम करने और पर्यावरण की देखभाल के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ तालमेल बिठाने के लिए बहुत जरूरी हैं। उत्पादकता से होने वाले विकास, संस्थागत समर्थन और तकनीक नवाचार के मेल से एक मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनी है जो मौसमी और बाजार के झटकों को झेलने में सक्षम है और साथ ही देश की पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।

संदर्भ

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying

- <https://nlm.udyamimitra.in/>
- https://dahd.gov.in/schemes/programmes/rashtriya_gokul_mission
- <https://bharatpashudhan.ndlm.co.in/>
- <https://www.pmsy.dof.gov.in/>
- <https://pmmkssy.dof.gov.in/pmmkssy/#/>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221582®=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2213532®=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2212290®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2101856®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2184705®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205031®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2225246®=3&lang=2>
- https://mofpi.gov.in/sites/default/files/KnowledgeCentre/Sector%20Profile/Sector_Profile_Fisheries.pdf
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221788®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2225763®=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2225760®=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelD=156127&ModuleId=3®=3&lang=1>

Ministry of Finance

- https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf
- <https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf>

Ministry of Rural Development

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2122478®=3&lang=2>

Ministry of Food Processing Industries (MoFPI)

- [https://mofpi.gov.in/sites/default/files/KnowledgeCentre/Sector%20Profile/Sector_profile_Meat_Poultry_\(1\)22.pdf](https://mofpi.gov.in/sites/default/files/KnowledgeCentre/Sector%20Profile/Sector_profile_Meat_Poultry_(1)22.pdf)

Lok Sabha and Rajya Sabha Questions

- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4180_nfzOf.pdf?source=pqals
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2500_MY7k37.pdf?source=pqals
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU4923_3Zmrxi.pdf?source=pqals
- https://sansad.in/getFile/annex/268/AU384_3ncA5j.pdf?source=pqars
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS371_0BKEvO.pdf?source=pqals
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2737_Zmswww.pdf?source=pqals
- https://sansad.in/getFile/annex/268/AU1181_cZK9ZJ.pdf?source=pqars
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU3729_txHX3D.pdf?source=pqals

Food and Agriculture Organisation (FAO)

- <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/beee9189-d92d-4a0d-86af-a1e3328c33d1/content>
- <https://www.fao.org/newsroom/detail/meat-eggs-and-milk-essential-source-of-nutrients-new-fao-report-says-250423/en>
- <https://www.fao.org/fsnforum/consultation/eggs-nutrition?page=1>

Niti Aayog

- <https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-10/Indias-Blue-Economy-Strategy-For-Harnessing-Deep-Sea-And-Offshore-Fisheries.pdf>
- https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-10/Reimagining_Agriculture_Roadmap_for_Frontier_Technology_Led_Transformation.pdf

Press Information Bureau

- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156873&ModuleId=3®=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2194086®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155298&ModuleId=3®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192114®=3&lang=2>

PIB Research

एपी /केसी/ एमपी/ डीके